RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 10 FEBRUARY TO 16 FEBRUARY 2021 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 25 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

तेल की कीमतों से जनता हलकान तो कंपनियां मालामाल

Page 2

रिलायंस को अमेरिका से मिला दुनिया का पहला 'कार्बन-न्यूट्रल' तेल

Page 3

आईसीएआर ने वायरस प्रतिरोधी मिर्च की किस्म विकसित की

Page 7

editoria!

उद्यमों का विस्तार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विस्तार के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है. वर्तमान में देश में ऐसे 6.5 करोड़ उद्यम हैं और सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में इनका योगदान 30 प्रतिशत है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य इस हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत करना है, ताकि ग्रामीण भारत के गरीबों का लाभ हो सके. उन्होंने गांवों के लिए उपयुक्त नवोन्मेषी और अनुसंधान आधारित तकनीकी विस्तार के लिए नीतिगत पहल की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है. गांवों में उद्यमिता का विस्तार किये बिना न तो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो सकता है और न ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव है. हमारे देश में गांवों में बसनेवाली बड़ी आबादी खेती और उससे संबंधित व्यवसायों पर निर्भर है. अधिकतर किसानों के पास बहुत कम खेतिहर जमीन है. बीते कुछ दशकों से अनेक कारणों से ग्रामीण भारत अनेक संकटों से जूझ रहा है. जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ और सूखे की बारंबारता बढ़ती जा रही है. पिछले कुछ सालों में खेती की पैदावार में बढ़ोतरी तथा उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित कर किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. आगामी वित्त वर्ष के बजट में गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी जोर दिया गया है. इस क्रम में उद्यमों का विकास भी आवश्यक है, ताकि खेती पर निर्भर लोगों की संख्या को कम किया जा सके तथा लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर रोजगार मुहैया हो सके. कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में शहरी कामगारों को अपने गांव लौटना पड़ा था. हालांकि आर्थिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने के बाद फिर लोग शहरों का रुख करने लगे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक नीतियों पर विचार किया जाना चाहिए. जैसा कि गडकरी ने बताया है, स्वतंत्रता के बाद से देश की आबादी का 30 प्रतिशत हिस्सा हमारे गांवों से शहरों की ओर पलायन कर चुका है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समुचित प्रगति नहीं हुई है. इस पलायन ने शहरों पर भी दबाव बढ़ाया है और कामगारों का जीवन स्तर वहां भी चिंताजनक है. यदि गांवों में ही उद्यमों का विस्तार हो, तो देश की अर्थव्यवस्था भी तेज गति से बढ़ेगी. हमारे देश के निर्यात में लघु व मध्यम उद्यमों का हिस्सा 40 प्रतिशत है तथा इस क्षेत्र में 11 करोड़ लोग कार्यरत हैं. कोरोना संकट से उबरने के क्रम में घोषित राहत पैकेज में इस क्षेत्र से जुड़े अनेक नियमों में बदलाव किया गया था तथा पूंजी भी उपलब्ध करायी गयी थी. बजट प्रस्ताव में भी इस संबंध में प्रावधान किये गये हैं. ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ाने के लिए सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए और लोगों को भी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उद्यमिता की ओर अग्रसर होना चाहिए.

1 साल की ऊंचाई पर पहुंचा कच्चा तेल

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

एजेंसी

अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल वायदा मंगलवार को ओपेक और उसके सहयोगियों द्वारा सप्लाई में कटौती करने की वजह से बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. इसके अलावा, ईंधन की मांग में सुधार से भी भावों को सपोर्ट मिला। 20 जनवरी के बाद से क्रूड ऑयल के भाव अपने उच्चतम स्तर पर हैं। लेकिन यह लगातार सातवां कारोबारी दिन है जिसमें कच्चे तेल के दामों में बढ़त बरकरार है। यह जनवरी 2019 के बाद कच्चे तेल में सबसे लंबे समय तक जारी रहने वाली तेजी है।

तेल उत्पादक देशों के संगठन ध्ईं ट्र के उत्पादन में कटौती करने और सबसे बड़े निर्यातक सऊदी अरब द्वारा अतिरिक्त आपूर्ति में कटौती करने की वजह से कच्चे तेल में तेजी आई है। इसके साथ ण्ध्क्ब्ऊ-19 के टीके प्रभावी होने से इस बात की संभावना अब बढ़ती जा रही है कि सब कुछ ठीक-ठाक चलने लगा तो तेल की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सब कुछ खुल जाने के बाद तेल ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। उसके बाद कच्चे तेल की मांग में सुधार आएगा। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड 61 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है, जो कि 24 जनवरी 2020 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (ICE) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के अप्रैल डिलीवरी अनुबंध में मंगलवार को बीते सत्र से 0.58 फीसदी की तेजी के साथ 61.05 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (Nymex) पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) के मार्च अनुबंध में बीते सत्र से 0.81 फीसदी की तेजी के साथ 58.44 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी के साथ तेल की मांग बढने की उम्मीदों से दाम में तेजी बनी हुई है, जिसे तेल के उत्पादन में कटौती से सपोर्ट मिल रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारत में पेट्रोल-डीजल के भावों पर देखा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम तीन दिन तक स्थिर रहने के बाद फिर से बढ़ गए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर चली गई हैं। पेट्रोल का भाव दिल्ली में पहली बार 87 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है. दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला संपन्न

प्लास्टिक उद्योगों के पंजीयन के लिए सलाहकार सेवा उपलब्ध करवाऐगा आईपीपीएफ

इंदौर। देश में लागू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के पालन में 4 साल बाद भी पुरी तरह से पालन शुरु नही हो सका है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर सख्त कार्यवाही की जाने लगी है। नियमों के अनुसार सभी ब्रांड ऑनर, प्लास्टिक प्रोडक्ट निर्माता, फूड- कन्फेक्शनरी निर्माता और पैकेजिंग मटेरियल निर्माताओं को मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल से पंजीयन करवाना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों की जानकारी देने के लिए मंगलवार को इंदौर में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के पालन के लिए कार्यशाला का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया। मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में इंडियन प्लास्टपैक फोकम सहयोगी संगठन था। इसमें बडी संख्या में प्लास्टिक उद्योगपति, रिसाइकलर, ब्रांड ऑनर, ट्रेडर और उत्पाद निर्माता मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक श्री योगेंद्र कुमार सक्सेना, इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल, इंदौर नगर पालिक निगम के कन्सलटेंट श्री असद वारसी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रिय अधिकारी श्री आरके गुप्ता और ने दीप प्रज्वलित किया शुभारंभ किया।

अपने प्रारंभिक उद्बोधन में मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रिय अधिकारी श्री आरके गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण पयार्वरण के लिए हानिकारक है इसका निपटान करना कठिन होता जा रहा है। उन्होनें बताया कि देश में प्रतिदिन 15 हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक का उपयोग होता है। लेकिन उसका मात्र 60 प्रतिशत ही रिसायकल हो पाता है। ऐसे में इसलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को लागू किया है। इसके नियमों के अनुरूप सभी को पंजीयन करवाना आवश्यक है। आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल ने बताया कि उद्योगों को वो चाहे किसी भी रूप में प्लास्टिक से जुडे है अपने पंजीयन आवश्यक करवाना चाहिए। इसके लिए इंडियन प्लास्ट पैक फोरम एक सलाहकार को अपने कार्यालय में नियुक्त करने जा रही है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला संपन्न

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पंजीयन करने और उनके नियमों के पालन के लिए उद्योगों को मदद करेगें। श्री बंसल ने बताया कि इंदौर जिला प्रशासन और इंदौर नगर पालिक निगम के साथ मिल कर ईपीआर के तहत नियमों का पालन करना सभी उद्योगों के लिए आवश्यक है। इसके लिए सभी अधिकारियों का सहयोग मिलता रहा है। आगे भी हम सब मिल कर इस दिशा में प्रयास करेगें।

आयोजन में मुख्य वक्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक योगेंद्र कुमार सक्सेना ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियम की जानकारी दी। उन्होनें बताया कि ऐसे ब्रांड ऑनर जो 2 या उससे अधिक राज्यों में व्यापार करते है उन्हें सेंट्रल पॉलुशन कंट्रोल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होनें बताया कि इंदौर के स्वच्छता के लिए किए कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में कई शहरों में अभी तक गीले और सुखे कचरे को अलग नही किया जा रहा है वही इंदौर में जीरो वेस्ट पर कार्य किया जा रहा है। उन्होनें प्लास्टिक रिसायकलिंग की प्रोसेस सहित अन्य जानकारी दी। नगर निगम के सलाहकार श्री असद वारसी ने बताया कि जिस प्रकार स्वच्छता में इंदौर मॉडल को पुरे देश में सराहना मिल रही है उसी प्रकार से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसबिलिटी के तहत भी इंदौर मॉडल बनाया गया है। जिसमें मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नियुक्त सभी पीआरओ को जोडा गया है। जैसे प्रदूषण बोर्ड में सभी प्लास्टिक उद्योगपति, रिसाइकलर, ब्रांड ऑनर, ट्रेडर और उत्पाद निर्माताओं का पंजीयन किया जा रहा है वैसे ही इंदौर नगर पालिक निगम में भी पंजीयन करवाना होगा। इस पुरे मैकेनिज्म को 6 माह में पुरे देश के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके तहत पीआरओ, रिसायकलर और नगर निगम मिल कर पुरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्य करेगें और इसका लाभ सभी को मिलेगा।इस मॉडल को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला को एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज मप्र के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने भी संबोधित किया। इस दौरान शक्ति इनवायरो एजेंसी और आरएसपीएल की ओर से भी प्रेजेंटेशन दिया गया। कार्यशाला में आईपीपीएफ के श्री सुभाष चतुर्वेदी, श्री रामकिशोर राठी, श्री प्रमोद सोमानी, श्री विकास बांगड सहित बडी संख्या में प्लास्टिक उद्योगपति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वैज्ञानिक श्री सुनील व्यास ने किया आभार प्रदर्शन श्री संजय जैन ने किया।

तेल की कीमतों से जनता हलकान तो कंपनियां मालामाल

BPCL के मुनाफे में 120 परसेंट का उछाल

नई दिल्ली। एजेंसी

BPCL Q3 results: पेट्रोल-डीजल की कीमतें (Petrol-Diesel Prices) लगातार आसमान छू रही हैं। इन पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। इस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत (Petrol Price) 87.30 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 93.83 रुपये प्रति लीटर हो गई। दिल्ली में डीजल का भाव (Diesel Price) 77.48 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 84.36 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों का ही नतीजा है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) का शुद्ध लाभ चालू 2020-21 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 120 परसेंट उछलकर 2,777.6 करोड़ रुपये पहुंच गया। बताया जा रहा है कि तेल के दाम में वृद्धि से पहले के बचे माल पर हुए लाभ के कारण Bharat Petroleum को फायदा हुआ है। इससे पहले 2019-20 की इसी तिमाही में कंपनी को 1,260.6 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बीबपीसीएल के निदेशक (वित्त) एन विजय गोपाल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में लाभ के रूप में तीसरी तिमाही काफी बेहतर रही है। कंपनी बिक्री के मामले में कोविड पूर्व स्तर पर आ गई है।

कम कीमत पर खरीदा कच्चा तेल

कंपनी को पहले के बचे तेल से 771 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। कंपनी ने ईंधन तैयार करने के लिए कच्चा तेल कम दाम पर खरीदा था, लेकिन बाद में दाम बढ़ने से उसे ऊंचे मूल्य पर बेचा। इसके अलावा कंपनी को 76 करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय लाभ भी हुआ है। बीपीसीएल की देश में चार रिफाइनरी हैं. उसने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में प्रत्येक एक बैरल कच्चे तेल को ईंधन में तब्दील करने पर 2.47 डॉलर का लाभ कमाया। कंपनी की बिक्री 1.4 प्रतिशत बढ़कर 86,579.9 करोड़ रुपये रही। पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1.110 करोड़ टन रही जो 2019-20 की इसी तिमाही में 1.102 करोड़ टन से अधिक है. ईंधन मांग 2020 के मुकाबले 2021 में बेहतर रहेगी तथा 2022 में इसमें और सुधार होगा।

ओमान ऑयल की हिस्सेदारी खरीदेगी बीपीसीएल

बीपीसीएल अगले 10 दिनों में बीना रिफाइनरी परियोजना में ओमान ऑयल कंपनी के शेयर खरीदेगी. कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी हिस्सेदारी की एक अलग बिक्री अगले महीने के अंत पूरी करने की उम्मीद कर रही है। बीपीसीएल के पास भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में 63.68 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसने मध्य प्रदेश के बीना में 78 लाख टन क्षमता वाली रिफाइनरी का निर्माण और परिचालन किया है। कंपनी के निदेशक (वित्त) एन विजयगोपाल ने बताया कि ओक्यू एसएओसी की 36.62 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए चर्चा पूरी हो चुकी है। हम अगले 10 दिनों में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा कर सकते हैं। ओक्यू एसएओसी पहले ओमान ऑयल कंपनी के रूप में जानी जाती थी।

लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल-डीज़ल के दाम

पेट्रोलियम मंत्री बोले- मिथ्या प्रचार की क़ीमतें उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी के साथ नई ऊंचाई पर पहुंच गईं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की अधिसूचना के मुताबिक, पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87.60 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 94.12 रुपये प्रति लीटर हो गई।

राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की कीमत बढ़कर 77.73 रुपये प्रति लीटर हो गई और मुंबई में कीमत 84.63 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गई। स्थानीय कर और भाड़े के आधार पर विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं।

राज्यसभा में तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार तेल कीमतों में राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क घटाने पर विचार नहीं कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले एक साल में पहली बार 61 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है। तेल कीमतों के उच्च स्तर पर होने के मिथ्या प्रचार का प्रयास किया जा रहा।

प्रधान पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रणाली के तहत नियंत्रित होती हैं और यह मिथ्या अभियान चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि ईंधन की कीमतें अब तक के उच्च स्तर पर है।

प्रधान ने राज्यसभा मे प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में कहा, 'पिछले 300 दिनों में करीब 60 दिन कीमतों में वृद्धि हुई और करीब 7 दिन पेट्रोल तथा 21 दिन डीजल की कीमतों में हमने कमी की है। करीब 250 दिनों तक हमने कीमतों में वृद्धि या कमी नहीं की है इसलिए यह मिथ्या प्रचार है कि यह अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। प्रधान ने कहा कि केंद्र ने उत्पाद शुल्क बढ़ाया है जबकि राज्यों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कीमतों में कमी भी की है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत एक संकेतक है लेकिन अंतरराष्ट्रीय उत्पाद की कीमत मानक है।

प्रधान ने कहा, 'हमारे देश में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने कर संग्रह को लेकर सतर्क हैं क्योंकि हर किसी की अपनी कल्याण प्रतिबद्धताएं और विकास संबंधी प्राथमिकताएं हैं, इसके लिए उन्हें इस तरीके से कुछ संसाधनों की आवश्यकता है। पेट्रोलियम कीमतों से कर संग्रह राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए एक परखा हुआ और खासा संग्रह है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जून 2010 और अक्टूबर 2014 में बाजार से जोड़ दिया गया है। तब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने अंतरराष्ट्रीय उत्पाद की कीमतों और बाजार की अन्य स्थितियों के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन और रुपये की विनिमय दर के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केवल वृद्धि ही नहीं की बल्कि कमी भी की है।

गेल का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 19 प्रतिशत बढ़ा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल (इंडिया) लि. का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 19 प्रतिशत बढ़कर 1,487.33 करोड़ रुपये रहा। प्रति शेयर लाभ 3.30 रुपये है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में शुद्ध लाभ 1,250.65 करोड़ रुपये था जो प्रति शेयर 2.77 रुपये बना था। कंपनी के अनुसार लाभ में वृद्धि का कारण पेट्रोरसायन क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन है। इससे गैस विपणन क्षेत्र में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हो गयी। कंपनी का पेट्रोरसायन कारोबार में कर पूर्व लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 434.08 करोड़ रुपये रहा। जबकि एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में उसे 8.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। हालांकि प्राकृतिक गैस विपणन बाजार को इस दौरान 73.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि एक साल पहले उसे इसी तिमाही में 466.52 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ हुआ था। गेल का कारोबार आलोच्य तिमाही में 13 प्रतिशत बढ़कर 15,386 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान (अप्रैल-दिसंबर) में गेल का शुद्ध लाभ 2,983 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले 2019-20 की इसी अवधि में उसे 3,602 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी का कारोबार चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान 41,057 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2019-20 की इसी अवधि में 54,021 करोड़ रुपये था। गेल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा कि इस साल कंपनी ने 450 किलो मीटर लंबी कोच्ची-मंगलूर तथा 348 किलो मीटर लंबी दोभी-दुर्गापुर गैस पाइपलाइन चालू की। इससे न केवल कंपनी के ग्राहक बढ़ेगे बल्कि गैस का खुदरा और पारेषण कारोबार भी बढ़ेगा।

रिलायंस को अमेरिका से मिला दुनिया का पहला 'कार्बन-न्यूट्रल' तेल

यह सौदा जलवायु-अनुकूलित कच्चे तेल के लिए एक नए बाजार के निर्माण में पहला कदम

नई दिल्ली। रिलायंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 'कार्बन-न्यूट्रल ऑयल' की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। यह कदम तब उठाया गया है जब यह कंपनी वर्ष, 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। अमेरिकी आपूर्तिकर्ता ने एक बयान में यह कहा कि, रिलायंस को 2 मिलियन बैरल खेप मिली है। ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स (ध्ध्न्), जो यूएस ऑयल मेजर ऑक्सिडेंटल की डिवीजन है, ने यह कार्बन-न्यूट्रल तेल रिलायंस को दिया था। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कंपनी, गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की

क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल-स्थान तेल शोधन परिसर संचालित करती है।

यह सौदा ऊर्जा उद्योग का पहला प्रमुख पेट्रोलियम शिपमेंट है, जिसके लिए समस्त क्रूड लाइफ साइकिल से जुड़े ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन, अंत उत्पादों के दहन के माध्यम से अच्छी तरह से, ऑफसेट किया गया है। इसे मैक्वेरी ग्रुप के कमोडिटीज और ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप (मैक्वेरी) के संयोजन से व्यवस्थित किया गया था।

तेल कार्बन-न्यूट्रल कैसे होगा?

ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स और मैकक्वेरी कच्चे तेल के उत्पादन, वितरण और शोधन के साथ जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ऑफसेट करेगा और कार्बन ऑफसेट क्रेडिट की निवृत्ति के माध्यम से परिणामी उत्पाद का उपयोग करेगा. इससे तेल 'कार्बन-न्यूट्रल' हो जाएगा।

रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने जुलाई, 2020 में रिलायंस को वर्ष, 2035 तक एक शुद्ध कार्बन शून्य कंपनी में बदलने की योजना का खुलासा किया था। ऑक्सीडेंटल, दूसरी ओर, ऐसी पहली अमेरिका-आधारित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी है, जिसने अपने उत्पादों के उपयोग के माध्यम से वर्ष, 2050 तक नेट-जीरो उँउ उत्सर्जन प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा की घोषणा की है। यह कंपनी पर्मियन बेसिन में 40 वर्षों से अपने संवर्धित तेल उगाही कार्यों में कार्बन-डाइऑक्साइड का उपयोग कर रही है।

मुख्य विशेषताएं

■एक बहुत बड़ा क्रूड कैरियर (VLCC) सी-पर्ल जिसमें कार्बन-तटस्थ/ न्यूट्रल तेल था, उसने 28 जनवरी को जामनगर में तेल उतारता है। ■ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स ने यह कहा है कि, तेल का निर्माण अमेरिकी पर्मियन बेसिन में ऑक्सीडेंटल द्वारा किया गया था और भारत में रिलायंस को दिया गया था। ■मैकक्वेरी ने ऑफसेट आपूर्ति और निवृत्ति के लिए पूरी व्यवस्था की थी। ■यह सौदा जलवायु-अनुकूलित कच्चे तेल के लिए एक नए बाजार के निर्माण में पहला कदम है। ■ यह एक तत्काल निष्पादन योग्य समाधान भी है जो लंबी अवधि के लिए, औद्योगिक पैमाने पर डिकार्बोनाइजेशन नीतियों में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है।

जीएसटी के बजट प्रावधानों में संशोधन की मांग

वाराणसी। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को चेतगंज स्थित बार कार्यालय में आम बजट पर परिचर्चा हुई। अधिवक्ताओं ने

जीएसटीआर 9सी की अनिवार्यता समाप्त करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया लेकिन कुछ अन्य प्रावधानों को वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार के पूर्व अध्यक्ष शरद त्रिपाठी ने की। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिटर्न 1 व 3बी में संशोधन की जरूरत है। बार के अध्यक्ष सुरेश सिंह व सचिव अरविंद चौरसिया ने कहा कि जीएसटी में आए दिन हो रहे परिवर्तन से व्यापारियों व कर सलाहकारों को दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में इन प्रावधानों पर संशोधन होना चाहिए। परिचर्चा में गंगेश पांडेय, विनयकांत मिश्रा, अशोक कुमार श्रीवास्तव, अश्विनी कुमार मिश्रा, अशोक सेठ, रामकुमार यादव, विनोद मिश्रा, अमित कुमार राय, संजय पांडेय, रोशन गुजराती, आशीष सेठ आदि शामिल हुए।

आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक करदाताओं को 1.91 करोड़ रुपये लौटाए

नई दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष में अबतक 1.87 करोड़ करदाताओं को 1.91 लाख करोड़ रुपये वापस किये हैं। इसमें से 1.84 करोड़ करदाताओं को 67,334 करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकर रिफंड जबकि कंपनी कर मामले में 2.14 लाख इकाइयों को 1.23 लाख करोड़ रुपये वापस किये गये। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, "सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2020 से आठ फरवरी, 2021 के दौरान 1.87 करोड़ करदाताओं को 1,91,015 करोड़ रुपये लौटाये।"

SBI रिसर्च का दावा

इस साल 7 फीसदी तक सिकुड़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था

मुंबई। एजेंसी

एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी और चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि के बाजवूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत संकुचित हो सकती है। इससे पहले एसबीआई शोध ने 2020-21 के दौरान जीडीपी में 7.4 प्रतिशत संकुचन की बात की थी। अप्रैल-सितंबर के दौरान अर्थव्यवस्था में 15.7 प्रतिशत संकुचन हुआ, लेकिन यदि एसबीआई का विश्लेषण सही साबित हुआ तो दूसरी छमाही में जीडीपी 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा कि 41 महत्वपूर्ण सूचकांकों में 51 प्रतिशत तेजी दर्शा रहे हैं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था के तीसरी तिमाही में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अर्थव्यस्था आर्थिक तेजी की पटरी पर लौट सकती है। उन्होंने कहा कि अंतिम आंकड़े सुखद आश्चर्य पैदा करने वाले हो सकते हैं। घोष ने कहा, "अब हमें उम्मीद है कि जीडीपी में गिरावट पूरे साल के लिए सात प्रतिशत रहेगी, जो हमारे पिछले पूर्वानुमान 7.4 प्रतिशत की तुलना में कम है। साथ ही चौथी तिमाही में वृद्धि सकारात्मक दिशा में लगभग 2.5 प्रतिशत हो सकती है।" एसबीआई रिसर्च ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि 11 प्रतिशत रहने के अपने अनुमान को बरकार रखा है। आर्थिक समीक्षा में अगले साल की वृद्धि 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबि भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान हे कि वृद्धि 10.5 प्रतिशत रहेगी।

सावधान ! टैक्स चोरी करने वाले ही नहीं अब सलाह देने वालों की भी संपत्ति होगी अटैच

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर आप टैक्स संबंधित कोई सलाह दे रहे है तो सावधान हो जाइए क्योंकि अब सिर्फ चोरी करने वालों की ही नहीं बल्कि सलाह देने वालों की भी संपत्ति अटैच होगी। एक्सपर्ट की मानें तो जीएसटी चोरी रोकने को बजट में सख्त प्रावधान किए हैं। ठहरिए अगर आप टैक्स संबंधित कोई सलाह दे रहे है तो सावधान हो जाइए क्योंकि अब सिर्फ टैक्स चोरी करने वालों की ही नहीं बल्कि सलाह देने वालों की संपत्ति भी अटैच होगी। एक्सपर्ट की मानें तो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी रोकने के लिए बीते दिनों जारी बजट में सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब टैक्स चोरी करने वाले ही नहीं उन्हें सलाह देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने का अधिकार जीएसटी कमिश्नर को मिला है। जो अपने विवेक के आधार पर कार्रवाई कर सकेंगे। हालांकि यह नया प्रावधान नोटिफिकेशन के बाद लागू होगा, लेकिन इसकी चर्चा अभी से होने लगी है।

बजट में बनाया जीएसटी पर सख्त कानून

जीएसटी विभाग सेक्शन 83 के तहत टैक्स चोरी करने वालों को नोटिस जारी कर टैक्स की वसूली करता है। एक्ट में एक जुलाई 2017 को हुए अमेंडमेंट के अनुसार अगर यह माना जाता है कि किसी करदाता ने टैक्स की चोरी की है तो उसकी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। बीते दिनों आए बजट में इसे और सख्त बनाया गया है। अब किसी भी फर्म की सर्च या जांच पर अगर जीएसटी कमिश्नर यह मानते हैं कि करदाता ने टैक्स चोरी की है तो राजस्व बढ़ाने के लिए वह संबंधित के बैंक खाता और संपत्ति पर होल्ड लगा सकते हैं।

इस प्रोटीन के कारण कम रही एशियाइ देशों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार

नई दिल्ली। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बहुत तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस एशियाई देशों में अपेक्षाकृत कम तेजी से फैला है। भारतीय विज्ञानियों ने इसके पीछे के कारण का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। विज्ञानियों का कहना है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों के शरीर में फेफड़ों की हिफाजत करने वाले एक प्रोटीन की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। यही उन लोगों में तेज संक्रमण का कारण बन जाता है।

भारतीय विज्ञानियों ने तोड़ा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में तेज संक्रमण का तिलिस्म

विज्ञान पत्रिका इंफेक्शन, जेनेटिक्स एंड इवॉल्यूशन में कोरोना वायरस के डी614जी म्युटेशन वाले वैरिएंट पर किए गए शोध को प्रकाशित किया गया है। वायरस का यह वैरिएंट बहुत तेजी से फैला था। जनवरी, 2020 में कुल संक्रमितों में से इस वैरिएंट से संक्रमित लोग मात्र 1.95 फीसद थे। वहीं, अगले 10 हफ्ते में यह वैरिएंट इतनी तेजी से फैला कि कुल संक्रमितों में इसकी हिस्सेदारी 64.11 फीसद पर पहुंच गई। बंगाल के कल्याणी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल

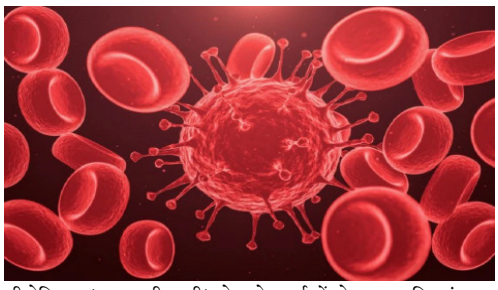

जीनोमिक्स (एनआइबीएमजी) के शोधकर्ताओं ने बताया कि संक्रमण के जिस स्तर तक पहुंचने में इस वायरस को यूरोप में 2.15 महीने और उत्तरी अमेरिका में 2.83 महीने का वक्त लगा, एशिया में उसी स्तर तक पहुंचने में 5.5 महीने लगे। विज्ञानियों ने बताया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों में अल्फा एंटी ट्रिप्सिन (एएटी) प्रोटीन की कमी संक्रमण में तेजी का अहम कारण है।

इटली और यूरोप के लोगों में एएटी की सर्वाधिक कमी

शोधकर्ता निधान के विश्वास ने कहा, 'कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन मानव कोशिकाओं के एसीई2 रिसेप्टर की मदद से संक्रमण फैलाता है। इसके डी614जी म्युटेशन में प्रसार की दोहरी क्षमता होती है।' शोध के दौरान पाया गया कि शरीर में न्यूट्रोफिल इलेस्टेज की मात्रा ज्यादा होने से वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता है। एएटी इसकी मात्रा को संतुलित करता है, जिससे वायरस के प्रसार को कम करने में मदद मिलती है। इटली और स्पेन के लोगों में एएटी की सर्वाधिक कमी पाई गई। इसलिए यहां के लोगों में वायरस सबसे ज्यादा तेजी से फैला।

एएटी सप्लीमेंट देकर कम की जा सकती है वायरस के प्रसार की गति

विश्वास ने जोर देकर कहा कि यह शोध केवल वायरस के प्रसार पर रोशनी डालता है। इसके आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वायरस का कौन सा स्ट्रेन ज्यादा घातक है। फिलहाल शोध के नतीजों से इन क्षेत्रों में लोगों को एएटी सप्लीमेंट देकर वायरस के प्रसार की गति कम करने का रास्ता खुल सकता है।

डॉलर के मुकाबले रुपया में 2 पैसे की मजबूती

नई दिल्ली। एजेंसी

विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज बुधवार यानी 10 फरवरी 2021 को मजबूती के साथ खुला। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की मजबूती के साथ 72.87 रुपये के स्तर पर खुला। वहीं, मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की मजबूती के साथ 72.89 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। डॉलर में कारोबार काफी समझदारी से करने की जरूरत होती है, नहीं तो निवेश पर असर पड़ सकता है। पिछले 5 दिनों के रुपये का क्लोजिंग स्तर -मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की मजबूती के साथ 72.89 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की कमजोरी के साथ 72.96 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की मजबूती के साथ 72.92 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी घटबढ़ के 72.96 रुपये

के स्तर पर बंद हुआ था। -बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया बिना किसी घटबढ़ के 72.96 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। डिमांड सप्लाई तय करता है भाव करेंसी एक्सपर्ट के अनुसार रुपये की कीमत पूरी तरह इसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इस पर असर पड़ता है। हर देश के पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, जिसमें वो लेन-देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अमरीकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है और ज्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर में ही चुकाते हैं। पहली वजह है तेल के बढ़ते दाम रुपये के लगातार कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल के बढ़ते दाम हैं। भारत कच्चे तेल के बड़े इंपोर्टर्स में एक है। भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसका बिल भी उसे डॉलर में चुकाना पड़ता है। दूसरी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजारों में अक्सर जमकर बिकवाली करते हैं। जब ऐसा होता है तो रुपये पर दबाव बनता है और यह डॉलर के मुकाबले टूट जाता है।

सीपीसीबी ने कोक, पेप्सिको, बिसलेरी, आदि पर लगाया 72 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। एजेंसी

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (एझँ) ने कोक, पेप्सिको और बिसलेरी पर प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को नहीं देने के मामले में भारी जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर करीब 72 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सीपीसीबी ने बिसलेरी पर 10.75 करोड़ रुपये, पेप्सिको इंडिया पर 8.7 करोड़ रुपये और कोका कोला बेवरेजेस पर 50.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

बाबा रामदेव की पतंजलि पर एक करोड़ का जुर्माना

कोक, पेप्सिको और बिसलेरी के अतिरिक्त बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर भी जुर्माना लगाया गया है। पतंजलि पर एक करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगी है। वहीं एक अन्य कंपनी पर 85.9 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

15 दिनों में भरना होगा जुर्माना

मालूम हो कि प्लास्टिक कचरों के मामलों में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) एक पॉलिसी पैमाना है, जिसके आधार पर प्लास्टिक का निर्माण करने वाली कंपनियों को उत्पाद के डिस्पोजल की जिम्मेदारी लेनी होती है। इस संदर्भ में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि सभी कंपनियों को 15 दिनों के भीतर ही जुर्माने की रकम का भुगतान करना होगा।

नौ महीने में सबसे अधिक रहा बिसलेरी का कचरा

प्लास्टिक के कचरे की मात्रा की बात करें, तो जनवरी से सितंबर 2020 तक बिसलेरी का प्लास्टिक का कचरा करीब 21 हजार 500 टन रहा है। इसलिए कंपनी पर पांच हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगा है। वहीं पेप्सिको और कोका कोला का कचरा क्रमशः 11,194 और 4,417 टन था।

ऑर्डर की समीक्षा कर रही है कंपनी- कोक

मामले में कोक के प्रवक्ता ने कहा है कि, 'कंपनी पूरे कंप्लायंस के साथ अपना ऑपरेशन चलाती है, जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कानूनों के तहत काम किया जाता है। कंपनी इस ऑर्डर की समीक्षा कर रही है और हम संबंधित अथॉरिटी के साथ मामले को सुलझाने का प्रयास भी करेगी करेंगे।'

फियो ने वित्त मंत्रालय से बजट में निर्यातकों के लिए कड़े प्रस्तावों पर विचार करने को कहा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

निर्यातकों की शीर्ष संस्था फियो ने बुधवार को वित्त मंत्रालय से बजट 2021 में सीमा शुल्क से संबंधित "कठोर और क्रूर" प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने को कहा, क्योंकि इससे निर्यातक समुदाय और एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में देश की क्षवि प्रभावित होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष एस के सराफ ने कहा कि वित्त विधेयक के माध्यम से लाए गए कुछ प्रावधानों का निर्यात पर "गंभीर" असर होगा। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क कानून की धारा 113 में प्रस्तावित संशोधन (जो अनुचित तरीके से निर्यात करने पर माल को जब्त करने के संबंध में है) पर फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह "कठोर और क्रूर" है। बजट में धारा 113 में एक उप-धारा को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी उत्पाद शुल्क या कर छूट या वापसी के दावे के तहत गलत दावा किया जाता है, तो माल जब्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि "गलत दावा" शब्द की कई व्याख्या हो सकती हैं और ऐसे में निर्यातक क्षेत्रीय संरचनाओं की दया पर निर्भर हो जाएंगे, चाहें छूट दरों की गलत गणना हो या किसी विशेष दर के तहत उत्पाद के वर्गीकरण के बारे में विवाद उत्पन्न हो। उन्होंने कहा, "छूट की दर उत्पाद मूल्य के मुकाबले दो प्रतिशत हो सकती हैं और इतने कम लाभ के लिए पूरे सामान को जब्त नहीं किया जाना चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह सीमा शुल्क कानून की धारा 113 के नए बनाए गए उप-धारा पर विचार करे।" सराफ ने यह भी कहा कि वित्त विधेयक ने आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में संशोधन कर आईजीएसटी (एकीकृत माल और सेवा कर) के भुगतान पर निर्यात की सुविधा को वापस ले लिया है। जब तक नए संशोधन अधिसूचित नहीं होते हैं , निर्यातकों के समक्ष दो विकल्प हैं। वे या तो आईजीएसटी का भुगतान करके निर्यात माल को बाहर भेजें या भुगता के लिए बांड/ सहमति पत्र (एलयूटी) भर कर निर्यात करें। सराफ ने कहा कि इन दोनों विकल्पों में निर्यातकों के लिए रिफंड हासिल करने में कोई झंझट नहीं होती। इस समय 60-70 प्रतिशत निर्यातक आईजीएसटी दे कर निर्यात करते हैं और उन्हें शिपिंग बिल के आधार पर आसानी से रिफंड हो जाता है। फियो अध्यक्ष ने निर्यात कारोबार की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वर्तमान रुझानों से लगता है कि 2021-22 में देश का निर्यात 285-290 अरब डालर तक पहुंच सकता है। अगले साल भारत को 340-350 अरब डालर का लक्ष्य रखना चाहिए। 2019-20 में निर्यात 314 अरब डालर था। फियो अध्यक्ष ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों के परिहार (छूट) की दरों को भी शीघ्र जारी किए जाने की अपील की ताकि निर्यातकों को अनुबंध करने में सहूलियत हो सके।

इस बार 'वैलेंटाइन डे' पर अपनों को बादाम के जरिये दें सेहत का तोहफा!

आईपीटी नेटवर्क

भारत। हर साल 14 फरवरी को प्यान्, स्नेह और दोस्तीह के उत्सल्व के रूप में 'वैलेंटाइन डे' मनाया जाता है। पूरी दुनिया में संत वैलेंटाइन के लिये यह दिन मनाया जाता है। लोग अपने प्यारे अंदाज से और कुछ तोहफे देकर अपना प्यायर अपनों के प्रति जाहिर करते हैं। इस साल महामारी को देखते हुए अपनों को बादाम जैसे कुछ समझदारी भरे तोहफे देने के बारे में सोचें। इससे ना केवल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आयेगी, बल्कि इससे आगे उनकी सेहत, इम्युनिटी और तंदुरुस्तीस में भी इजाफा होगा। बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, जिंक जैसे 15 पोषक तत्वोंभ का स्रोत है। दिल की सेहत , , त्व चा की सेहत और वजन को नियंत्रित रखने , में फायदा देने वाले ये बादाम ब्ल1ड शुगर , को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

शीला कृष्णाहस्वामी, न्यूट्रिशन एवं वेलनेस कंसल्टें ट का कहना है, ''वैलेंटाइन डे' के दिन तोहफों का लेन-देन एक परंपरा है, लेकिन आमतौर पर यह चॉकलेट और शक्करर से भरपूर चीजों तक ही सीमित होता है, जोकि हमारी सेहत के लिये अच्छेण नहीं होते हैं। मेरा सुझाव है कि अपनों के लिये तोहफे लेते समय खाने की ऐसी चीजें चुनें जो स्वा द में अच्छे होने के साथ-साथ सेहत के लिये भी फायदेमंद हों।

जानी-मानी फिटनेस और सेलिब्रिटी इंस्ट्रलक्टंर, यास्मी न कराचीवाला के अनुसार, 'वैलेंटाइन डे' अपनों के साथ मनाने का एक अच्छार समय होता है और वे जिस परवाह के हकदार हैं, उसे दिखाने का भी। मुझे लगता है कि ऐसा करने के कई सारे तरीके हैं और इसके लिये किसी तामझाम वाले डिनर का प्लाहन बनाने या फिर किसी महंगे हॉलीडे पर ले जाने की जरूरत नहीं होती। अपने पार्टनर या अपनों की सेहत के लिये जिम की एक मेंबरशिप खरीद लेना, ऑनलाइन पिलेट्स क्लानस में उनका नाम इनरॉल कर देना या फिर उन्हें अपनी ज्यौदा से ज्यारदा देखभाल के लिये प्रेरित करना और उनके साथ नियमित रूप से वर्कआउट करने जैसी छोटी-छोटी चीजों से भी इसे किया जा सकता है।

रितिका समद्दर, रीजनल हेड-डाइटेटिक्सं, मैक्सा हेल्थरकेयर-दिल्ली का कहना है, ''वैलेंटाइन डे' पर तोहफा देना सबसे महत्वनपूर्ण होता है और आस-पास ढेरों विकल्पे होने पर सोच में पड़ना आसान है। मैं हमेशा से ही ऐसे तोहफे देने पर जोर देती हूं जोकि उसे पाने वाले की सेहत को बेहतर बनाने का काम करें और मेरा सुझाव है कि बादाम दिया जाना चाहिये।

माधुरी, रुइया, पिलेट्स एक्सीपर्ट एवं डाइट तथा न्यूजट्रिशन ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'वैलेंटाइन डे' के दिन काफी सारे लोग हाई कैलोरी से भरपूर खाना खा लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में डिनर ना करके और अपने पार्टनर के लिये घर पर खाना तैयार करके इस स्थिति से बच सकते हैं। इसमें आप बादाम जैसी सेहतमंद चीजों को मिला सकते हैं, क्योंसकि इसे आसानी से और झटपट स्वापदिष्ट बनाया जा सकता है। बादाम के साथ सारे भारतीय मसाले अच्छीह तरह घुलमिल जाते हैं। आप हेल्दी तथा स्वासदिष्टि पकवान बनाने के लिये अपने पार्टनर के पसंदीदा मीठे पकवान में बादाम मिला सकते हैं।'' आइये, इस 'वैलेंटाइन डे' अपनों के साथ मिलकर बादाम से सेहतमंद रहने का साझा संकल्पन लें! यहां बादाम से बनायी गयी रेसिपी दी गयी है जोकि आपके अपनों के 'वेलेंटाइन डे' को खास बना देगी।

पोषण से जुड़ी जानकारी

कैलोरी 3448 प्रोटीन 104 ग्राम
कुल फैट 243.3 ग्राम सैचुरेटेड 21 ग्राम
मोनोसैचुरेटेड 147.3 ग्राम पॉलीसैचुरेटेड 71.8 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट 260.7 ग्राम फाइबर 44.9 ग्राम
कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम सोडियम 11 मिलीग्राम
कैल्शियम 2506 मिलीग्राम मैग्नीयशियम 1423 मिलीग्राम
पोटेशियम 3268 मिलीग्राम विटामिन ई 105.1 मिलीग्राम

पीएचई विभाग के पाइप निर्माण में बदलाव से स्थानीय पॉलिमर निर्माता कंपिनयों पर असर

अतिरिक्त मुख्य सचिव से मिला प्रतिनिधी मंडल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मप्र जल स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले पाइप के रॉ मटेरियल में बदलाव किए जाने पर स्थानीय पॉलिमर निर्माता कंपनियों ने शासन के समक्ष अपनी बात रखी। मध्यप्रदेश में जल निगम द्वारा जारी किए जाने वाले काले पाईप के टेंडरों में किए गए बदलावों को लेकर इंडियन प्लास्ट पैक फोरम का प्रतिनिधियों मंडल भोपाल में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मिला। आईपीपीएफ के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल के नेतृत्व में प्रमुख पॉलीमर निर्माता कंपनियों के डीजीएम और अन्य अधिकारियों ने एडीशनल चीफ सेक्रेट्री मध्य प्रदेश शासन श्री मलय श्रीवास्तव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान पाइप में एचडीपीई रेजिंस एंड कार्बन ब्लैक मास्टर बैच को शामिल करने की मांग की गई। पूर्व में शामिल रहने वाले इस मटेरियल को हटा कर प्री कॉम्पाउंड ब्लैक पीई मटेरियल कर दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए श्री सचिन बंसल ने बताया कि देश में उत्पादन होने वाले नेचुरल पॉलीमर को हटा कर प्री कंपाउंड ब्लैक मटेरियल करने से स्थानीय निर्माताओं से सरकारी सप्लाई में काम करने के अवसर खत्म हो जाएगें। उन्होंने बताया कि जल निगम के टेंडर मेंनेचुरल पीई मटेरियल को पुनः शामिल करने के लिए प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड,गेल ओपॉल सहित अन्य कंपनियों के अधिकारी उपस्थिति थे। इस मीटिंग के लिए आईपीपीएफ के सदस्य श्री सचिन पारिख का सराहनीय योगदान रहा। चर्चा में सीपेट के श्री संदेश जैन विशेष रूप से उपस्थिति थे। इस दौरान जल निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

जापान, आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की रूपरेखा तैयार की जा रही है: गोयल

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जापान और आसियान के साथ संबंधित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा शुरू करने की एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को यह कहा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा चल रही है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''जापान और अन्य आसियान देशों के साथ एफटीए की त्वरित समीक्षा की रूपरेखा तैयार करने पर काम चल रहा है।'' अमेरिका के साथ प्रस्तावित लघु व्यापार सौदे के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि हमें अमेरिका के नये व्यापार मंत्री का इंतजार करना होगा। उन्हें भी सौदे पर वहां की नयी सरकार का रुख जानना होगा। हमारे पास भी इस बारे में कुछ विचार हैं। नयी अमेरिकी सरकार के साथा बातचीत शुरू होने के बाद ही इस बारे में कोई टिप्पणी की जा सकती है।''

मार्च के अंत तक नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी 61.65% हिस्सेदारी बेचेगी भारत पेट्रोलियम

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड निजीकरण की ओर बढ़ते हुए ऑयल इंडिया और असम सरकार को नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में अपनी 61.65 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना को मार्च के अंत तक पूरा कर लेगी। कंपनी के डायरेक्टर (Finance) एन विजयगोपाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एन विजयगोपाल ने सोमवार को कहा कि योजना के अनुसार, ओआईएल एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का कंसोर्टियम 49 फीसदी का अधिग्रहण करेगा और बाकी 13.65 प्रतिशत असम सरकार को बेचा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी का 31 मार्च तक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लेन-देन का पूरा होना आवश्यक सरकारी मंजूरी के सौदे के अधीन है।

विजयगोपाल ने इस दौरान बताया कि भारत पेट्रोलियम अगले 10 दिनों में बीना रिफाइनरी परियोजना में ओमान ऑयल कंपनी के शेयर खरीदेगी। जिसके लिए कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में अपनी हिस्सेदारी की एक अलग बिक्री अगले महीने के अंत पूरी करने की उम्मीद कर रही है। BPCL के पास भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में 63.68 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसने मध्य प्रदेश के बीना में 78 लाख टन क्षमता वाली रिफाइनरी का निर्माण और परिचालन किया है।

विजयगोपाल ने तिमाही परिणाम के बाद पत्रकारों से कहा कि ओक्यू एसएओसी (OQ S.A.O.C.) की 36.62 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए चर्चा पूरी हो चुकी है। हम अगले 10 दिनों में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा कर सकते हैं। OQ S.A.O.C. पहले ओमान ऑयल कंपनी के रूप में जानी जाती थी। हालांकि उन्होंने अधिग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारियां नहीं दी। BPCL अभी निजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। हालांकि निजीकरण से पहले कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) से बाहर निकल जाएगी।

यह इसलिए हिस्सेदारी बेच रही है, क्योंकि सरकार ने असम शांति समझौते के अनुसार नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने पर सहमति व्यक्त की है। 2021-22 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा है। इस क्रम में सरकार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) में अपनी पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है।

वेदांता ग्रुप ने कहा है कि उसने BPCL में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रारंभिक अभिरुचि पत्र (expression of interest) दाखिल कर दिया है। भारत की दूसरे सबसे बड़े ईंधन रिटेलर कंपनी में वेदांता की दिलचस्पी उसके अपने मौजूदा तेल और गैस कारोबार के साथ तालमेल रहने के कारण है। इस बिक्री में असम की नुमालीगढ़ रिफाइनीर में BPCL की 61.65 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है।

मां सरस्वती की आराधना से ये 3 भक्त बन गए थे विद्वान

16 फरवरी को वसंत पंचमी है। यह दिन देवी सरस्वती के जन्मोत्सव यानी वसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक शास्त्रों इस दिन उनकी पूजा-अर्चना करने का विधान बताया गया है। हिंदू धर्मग्रंथों में देवी सरस्वती के 3 ऐसे भक्त रहे हैं। जो पहले मंद बुद्धि थे, लेकिन मां सरस्वती की आराधना के बाद वह विद्वानों की श्रेणी में वरिष्ठ क्रम में आते हैं। यह तीन भक्त कालिदास, वरदराजाचार्य और वोपदेव हैं, जो बचपन में अत्यल्प बुद्धि के थे।

कालिदास: महाकवि कालिदास ने हिंदू पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर संस्कृत में रचनाएं कीं। अभिज्ञानशाकुंतलम् कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम् कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पनाशक्ति की विलक्षणता पढ़ी जा सकती है। उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है।

वरदराज: वरदराज जिन्हें वरदराजाचार्य भी कहा जाता है। वह संस्कृत व्याकरण के महापंडित थे। वे महापंडित भट्टोजि दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोजि दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी पर आधारित उन्होंने तीन ग्रंथ रचे जो क्रमशः मध्यसिद्धान्तकौमुदी, लघुसिद्धान्तकौमुदी तथा सारकौमुदी हैं।

वोपदेव: वोपदेव जी विद्वान्, कवि, वैद्य और वैयाकरण ग्रंथाकार थे। इनके द्वारा रचित व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ 'मुग्धबोध' है। इनका लिखा कविकल्पद्रुम तथा अन्य अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ये 'हेमाद्रि' के समकालीन थे और देवगिरि के यादव राजा के दरबार के मान्य विद्वान थे।

प्रभु श्रीराम ने की थी इन संतों की सेवा

प्रभु श्रीराम ने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ 'रामायण' में ही नहीं, देशभर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। विश्वामित्र को ताड़का और सुबाहु के आतंक से मुक्ति दिलाई। सुंदरवन में ऋषि रहते थे। सुंदरवन को पहले ताड़का वन कहा जाता था। राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली थी। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। इसके अलवा उन्होंने वाल्मीकि, अत्रि और ऋषि मतंग ही नहीं, सैकड़ों ऋषियों के आश्रम को उन्होंने वेद ज्ञान और ध्यान के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया था।

उन्होंने चित्रकूट में रहकर धर्म और कर्म की शिक्षा-दीक्षा ली। यहीं पर वाल्मीकि और मांडव्य आश्रम था। यहीं पर से राम के भाई भरत उनकी चरण पादुका ले गए थे। चित्रकूट के पास ही सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्रीराम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहां के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्रीराम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। दंडक वन में ही उन्होंने कबंध, विराध, मारीच, खर और दूषण का भी वध किया था। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस दंडकारण्य इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल हैं। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किमी तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है।

सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों पर असर

12 फरवरी 2021 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के शुभ प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है, जबकि खराब स्थिति होने से मान-सम्मान में कमी, पिता को कष्ट और नेत्र पीड़ा का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं 12 फरवरी 2021 से सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही किस राशि पर कैसा होगा असर...

मेष राशि- सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। इस परिवर्तन से मेष राशि के जातकों की आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और लाभ के कई मार्ग खुलेंगे। आपको शासन और प्रशासन दोनों का सहयोग मिलता नजर आ रहा है।

वृषभ राशि- सूर्य के इस राशि परिवर्तन से वृषभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में असीमित अधिकार मिल सकते हैं। आपको मान सम्मान के साथ साथ कार्य क्षेत्र में लोगों पर नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन की वजह से मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपको धन और धान्य का लाभ होगा और कार्यों में सफलता के चलते आपके आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी होगी।

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर इस राशि के जातकों को अपने पिता की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपका कोई पुराना राज बाहर आ सकता है। जिसका असर आपकी छवि पर पड़ सकता है। सतर्क रहें।

सिंह राशि- सूर्य के राशि परिवर्तन का असर मुख्य रूप से सिंह राशि के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और दांपत्य जीवन पर पड़ सकता है। पहले के मुकाबले खुद को ज्यादा चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे और पुरानी किसी स्वास्थ्य समस्या से आपको निजात मिलेगी।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी तो कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें।

तुला राशि- सूर्य के राशि परिवर्तन करने से तुला राशि को शासन पक्ष से लाभ मिल सकता है। प्रेम के मामले में यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। छोटी सी बात आपके रिश्ते को खराब कर सकती है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों के भीतर इस समय अहम की भावना आ सकती है। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए आप बढ़-चढ़कर बातें करेंगे। हालांकि यह समय कार्यक्षेत्र के लिहाज से बेहतर है।

धनु राशि- आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और भाग्य की कृपा से आपके सभी रूके हुए काम बनेंगे। आपको इस समय लाभ मिलने के साथ समाज में अच्छा मान-सम्मान भी प्राप्त होगा।

मकर राशि- मकर राशि के लिए इस राशि परिवर्तन की वजह से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।आप अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करेंगे। जिसकी वजह से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।

कुंभ राशि- सूर्य के राशि परिवर्तन करने से कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुंभ राशि के जातक इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें।

मीन राशि- मीन राशि के जातकों को इस दौरान अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन नौकरी के लिए किए गए सभी प्रयासों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।

दर्पण को बेडरूम में इस दीवार पर लगाना शुभ

आज हर कोई समस्याओं से घिरा हुआ है। किसी को अपने करियर की चिंता है तो किसी को अपनी सेहत की। बाधाएं तो हर किसी के जीवन में आती रहेंगी, लेकिन फेंगशुई और वास्तु में ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय सुझाए गए हैं।

■फेंगशुई में माना जाता है कि दर्पण घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दर्पण सदैव उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। घर या प्रतिष्ठान में नुकीले या तेजधार वाले दर्पण कभी नहीं लगाने चाहिए। शयन कक्ष में यदि दर्पण लगाना है तो उत्तर या पूर्व की दीवार पर ही लगाना चाहिए। ■शयनकक्ष में बेड के ठीक सामने आईना लगाना अशुभ माना जाता है। बेड के ठीक सामने दर्पण होने से पति-पत्नी के बीच टकराव पैदा हो जाता है। दर्पण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए इसे ढंककर रखना चाहिए। रात में तो दर्पण आखों को नजर नहीं आना चाहिए। ■दर्पण का टूटना अशुभ माना जाता है । माना जाता है कि दर्पण के टूटने पर जैसे कोई मुसीबत इस पर टल गई हो। टूटे हुए शीशे को तुरंत फेंक देना चाहिए। ■घर की पूर्व दिशा में धातु से निर्मित वस्तुएं न रखें। घर में अविवाहित युवक दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं सोएं। काले रंग का पहनावा न पहनें। एक से अधिक दरवाजे वाले कमरे में नहीं सोना चाहिए।

'टोने' व 'टोटके' में जानिए क्या है अंतर

टोने-टोटके, यह शब्द हम कई बार सुनते हैं। सुनने में यह शब्द थोड़े अजीब जरुर लगते हैं लेकिन यह तंत्र शास्त्र के एक सिक्के के दो पहलू हैं बस इनकी क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। साधारण भाषा में कहें तो दैनिक जीवन में किए जाने वाले छोटे-छोटे उपाय टोटका कहलाते हैं जबकि टोने विशेषतः समय पडने पर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। वह किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए किए जाते हैं। जानते हैं इनके बीच क्या अंतर है।

टोटका

जब हम किसी यात्रा पर जा रहे हो और अचानक कोई छींक दे तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। ऐसे ही जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम थोड़ी देर रुक कर चलते हैं या रास्ता बदल लेते हैं। यात्रा पर किसी विशेष कार्य पर जाने से पहले पानी पीना या दही का सेवन करना, यह सब टोटका कहलाता है। टोटके साधारण प्रभावशाली होते हैं व इनके निराकरण भी साधारण ही होते हैं।

टोना

विशेष कार्य सिद्धि के लिए हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या किसी अन्य मंत्र का जप विधि-विधान से जप करना टोना कहलाता है। किसी यंत्र अथवा वस्तु को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना भी टोना का ही एक रूप है। टोना टोटके का ही जटिल रूप है जो किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए पूरे विधि-विधान से किया जाता है। टोना के लिए समय, मुहूर्त, स्थान आदि सब कुछ नियत होता है।

दलहन आयात की जरूरत कम होने से सालाना 15,000 करोड़ रुपये की बचत: तोमर

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत, दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि दलहन आयात पर निर्भरता कम हुई है और देश को प्रति वर्ष 15,000 करोड़ रूपए से अधिक की बचत हो रही है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे तोमर यहां विश्व दलहन दिवस पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि पिछले पांच-छह साल में किसानों व वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम एवं केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण देश ने अपने दलहन उत्पादन को 140

लाख टन से बढ़ाकर 240 लाख टन कर लिया है।

उन्होंने कहा, " हमें भविष्य की आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान देना होगा। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2050 तक लगभग 320 लाख टन दलहन की आवश्यकता होगी।" इस मौके पर तोमर ने आईआईपीआर के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल व बीकानेर में कार्यालय व प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन किया, साथ ही आईआईपीआर के क्षेत्रीय केंद्र खोरधा (ओडिशा) की आधारशिला रखी। इस अवसर पर 'आत्मनिर्भरता एवं पोषण सुरक्षा' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जा रही है। इसमें 700 से अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, नीति निर्धारक, छात्र-छात्राएं एवं किसानबंधु शामिल हो रहे हैं, जो दलहन व पोषण सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने लोगों के स्वास्थ्य पर दलहनी फसलों के अच्छे प्रभाव को देखते हुए विश्व दलहन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इससे विश्व का ध्यान दलहनी फसलों को बढ़ावा देने पर जाएगा व इसमें हमारे सामूहिक प्रयासों को बल मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में गेहूं व धान की खरीद तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होती आ रही थी, लेकिन दलहन व तिलहन की खरीद की व्यवस्था नहीं थी, केंद्र सरकार ने किसानों को आय समर्थन के लिए इन्हें भी एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि छह साल में दालों के एमएसपी को 40% से 73% तक बढ़ाया गया है, जिसका लाभ निश्चित ही किसानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए भी दलहन पर और काम करने की जरूरत है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुख्य भूमिका है, कृषि वैज्ञानिक अनेक किस्में देश को उपलब्ध करा रहे हैं, जिनसे उत्पादन व उत्पादकता दोनों बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आईसीएआर ने वायरस प्रतिरोधी मिर्च की किस्म विकसित की

बेंगलुरु। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बेंगलुरु स्थिति भारतीय आगवानी शोध संस्थान (आईआईएचआर) ने वायरस प्रतिरोधी मिर्च की एक नयी किस्म विकसित की है। आईआईएचआर बाजार में सीधे इस किस्म को अब परखने के लिए इसे देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को देगा। स्थान-विशेष के केवीके के मिले परिणामों के आधार पर, उस विशेष क्षेत्र में मिर्च के बीज बाजार में जारी किए जा सकते है। आईआईएचआर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ के माधवी रेड्डी ने बुधवार को राष्ट्रीय बागवानी मेला -2021 के दौरान बताया, "हमने लीफ कर्ल वायरस प्रतिरोधी एक मिर्ची विकसित की है।" लीफ कर्ल के प्रकोप से मिर्च की पत्तियां ऐंठ जाती है। यह वायरस रायचूर में ज्यादा प्रचलित है। वहां से इसे निकाल कर इसके प्रभाव पर अनुसंधान कर के नयी किस्म विकसित की गयी है।

सरकार नेशनल फर्टिलाइजर्स में अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी

नयी दिल्ली। सरकार नेशनल फर्टिनाइजर्स लि. (एनएफएल) में अपनी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री पेशकश के जरिये बेचेगी। शेयर बिक्री प्रबंधन के लिये मर्चेन्ट बैंकरों से बोलियां आमंत्रित की गयी हैं। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक अधिसूचना में कहा कि बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि दो मार्च है। मौजूदा बाजार भाव पर कंपनी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री से सरकारी खजाने को करीब 400 करोड़ रुपये मिलेंगे। एनएफएल का शेयर बुधवार को बीएसई में 2.33 प्रतिशत मजबूत होकर 41.80 पर बंद हुआ। सरकार की कंपनी में 74.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल-सितंबर के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 198 करोड़ रुपये था। एनएफएल का गठन 1974 में हुआ और उसके कर्मचारियों की संख्या 3,339 है। कंपनी के फिलहाल पांच गैस आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र हैं।

भारत के सोया खली निर्यात ने जनवरी में लगाई छह गुना की छलांग

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अंतरराष्ट्रीय मांग में इजाफे का सिलसिला बरकरार रहने के चलते जनवरी के दौरान भारत का सोया खली निर्यात लगभग छह गुना उछाल के साथ 3.36 लाख टन पर पहुंच गया। जनवरी 2020 में देश से 58,000 टन सोया खली का निर्यात गया था। प्रसंस्करणकर्ताओं के इंदौर स्थित संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के एक आला अधिकारी ने बुधवार को ये आंकड़े जारी किए। सोपा के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने यह भी बताया कि इस साल जनवरी में इंडोनेशिया (79,375 टन), फ्रांस (70,500 टन) और जर्मनी (48,765 टन) भारतीय सोया खली के सबसे बड़े आयातकों में शामिल रहे। पाठक ने बताया कि भारतीय सोया खली के भाव अमेरिका, ब्राजील और अर्जेन्टीना के इस उत्पाद के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। इससे भारत का सोया खली निर्यात बढ़ रहा है। उन्होंने अनुमान जताया कि मौजूदा तेल विपणन वर्ष (अक्टूबर 2020-सितंबर 2021) में भारत का सोया खली निर्यात दोगुना बढ़कर 18 लाख टन पर पहुंच सकता है। पिछले तेल विपणन वर्ष में देश से 8.62 लाख टन सोया खली का निर्यात किया गया था। प्रसंस्करण संयंत्रों में सोयाबीन का तेल निकाल लेने के बाद बचने वाले उत्पाद को सोया खली कहते हैं। यह उत्पाद प्रोटीन का बड़ा स्त्रोत है। इससे सोया आटा और सोया बड़ी जैसे खाद्य पदार्थों के साथ पशु आहार तथा मुर्गियों का दाना भी तैयार किया जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार : 590 बिलियन डॉलर के रिकार्ड स्तर पर आया

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह के दौरान 4.85 अरब डॉलर की बढ़त के साथ ही 590.18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में दी गई है। इससे पहले 22 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.091 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 585.334 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया था। हालांकि 15 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.839 अरब डॉलर कम होकर 584.242 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया था। वहीं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के पास रिकॉर्ड 590.18 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। यह साल भर पहले की तुलना में 119 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ा है।

जानिए आरबीआई के आंकड़े

रिजर्व बैंक क तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन समय में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त आई है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, कुल विदेशी मुद्रा भंडार का काफी बड़ा हिस्सा होती है। आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार एफसीए 5.03 अरब डॉलर बढ़ाकर 547.22 अरब डॉलर के स्तर पर स्तर पर आ गया है। एफसीए को दिखाया डॉलर के रूप में जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्रा संपत्तियां भी शामिल होती है।

भारत का स्वर्ण भंडार कम हुआ

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी

को समाप्त सप्ताह के दौरान भारतका स्वर्ण भंडार का मूल्य 16.4 करोड़ डॉलर घटकर 36.459 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। वहीं देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मिला विशेष आहरण अधिकार 40 लाख डॉलर कम होकर 1.51 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। वहीं आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा भंडार भी 60 लाख डॉलर घटकर 5.16 अरब डॉलर हो गया

जानिए अनुराग ठाकुर का बयान

वहीं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के पास रिकॉर्ड 590.18 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। यह साल भर पहले की तुलना में 119 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ा है। इन्होंने कहा कि इसके साथ ही देश अब शुद्ध ऋणदाता बन गया है। शुद्ध ऋणदाता ऐसी स्थिति को कहा जाता है, जब विदेशी मुद्रा भंडार कुल विदेशी कर्ज से अधिक हो जाए। भारत के ऊपर 554 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि भारत अगले चार-पांच वर्ष में पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

नमकीन मिठाई और चिप्स निर्माताओं के लिए अनिवार्य सदस्यता शिविर में बोले वक्ता

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश, नमकीन मिष्ठान एसोसिएशन इंदौर, जिला प्रशासन एवं अन्य संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को सीए फाउंडेशन सभागृह में नमकीन, मिठाई एवं चिप्स निर्माता उद्यमियों के लिए अनिवार्य सदस्यता एवं खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर "खाद्य गौरव 2021" का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय एवं इंदौर जिला कलेक्टर श्री मनीषसिंह थे।

एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया और नमकीन मिष्ठान एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास जैन ने कहा कि पूर्व में भी नमकीन निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें जागरूक किया गया था, यह दूसरा प्रयास पुनः आपकों जोडने तथा जागरूकता के लिए किया जा रहा है, इसका लाभ लेवें। कलेक्टर महोदय् के मार्गदर्शन में प्रशासन लगातार सहयोग की भूमिका में है इसके लिए आपको भी खाद्य सुरक्षा के मानकों को फालो करना होगा। यदि कोई संशय है तो त्वरित प्रशिक्षकों व प्रशासकीय अधिकारियों से सम्पर्क करें, लेकिन कोई मिलावट कर उत्पाद निर्माण न करें।

विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय ने अपने वक्तव्य में कहा कि समय के साथ अपने व्यवसाय में बदलाव करे, तकनीकी का उपयोग करे साथ ही सिस्टम को स्वच्छ बनाना है ऐसा प्रण ले। आपने उद्योगपतियों से कहा कि मै पूरे विश्वास के साथ आपके सहयोग के लिए तत्पर हुं।

कलेक्टर श्री मनीषसिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी के आव्हान पर वर्तमान में मिलावट मुक्त अभियान चलाया जा रहा है तथा इसी तारतम्य में

आज की कार्यशाला का भी यह आयोजन हो रहा है। आपने कहा कि निर्माताओं को एसोसिएशन के अनिवार्य पंजीयन के साथ उत्पाद निर्माण एवं कार्यस्थल दोनों की गुणवत्ता पर फोकस करना होगा किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार को नही करना है अन्यथा इसमें भारी पेनल्टी है। अज्ञानता वश जो कार्य हुए है उनमें सुधार के साथ असंगठित क्षेत्र के निर्माताओं को भी इस अभियान से जोडना होगा। आपने एसोसिएशन से आग्रह किया कि गलती करने वालों की जानकारी आप प्रशासन को देवें, उनमें बदलाव के प्रयास प्रशासन करेगा। आपने विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय के उद्योगों को सहयोग के विश्वास का भी समर्थन करते हुए कहा कि प्रशासन आपके साथ है, आपके मार्गदर्शन के लिए एसोसिएशन व प्रशासन दोनो का सहयोग लेवे।

नमकीन मिष्ठान्न एसोसिएशन के सचिव श्री अनुराग बोथरा ने आज के आयोजन की जानकारी के साथ प्रशासन के समक्ष जीआई टेग की मांग रखी तथा प्रशासन से सख्ती में राहत की अपील की। आपने कहा कि जो असंगठित है उन्हें संगठित करने का प्रयास करेगे। आपने उद्योगपतियों से यह संकल्प दोहराया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नही होती। कार्यशाला में बंगाल से माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं नई दिल्ली से सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने इस कार्यशाला के लिए शुभकामना संदेश दिये तथा इस अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया।

श्री प्रमोद डफरिया ने बताया कि आज के शिविर में ही 175 से अधिक निर्माताओं द्वारा 'शपथ पत्र के साथ पंजीयन किया गया यह इस कार्यक्रम की बडी उपलब्धि रही है। आगे भी पंजीयन प्रक्रिया के प्रयास जारी रहेगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अभय बेडेकर, एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जैन, नमकीन मिष्ठान एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विकास जैन, श्री अनील पालीवाल, श्री प्रमोद जैन, श्री अमित कुमठ सहित 300 से अधिक संख्या में नमकीन निर्माता, स्टॉल ओनर्स, अन्य संगठनों के प्रतिनिधि व गणमान्यजन उपस्थिति थे। कलेक्टर श्री मनीषसिंह जी ने कार्यस्थल पर लगे 60 से अधिक स्टॉल का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम का संचालन एआयएमपी के उपाध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने करते हुए प्रशासन के समक्ष मांग रखी की इंदौर में फूड टूरिज्म डेवलप करें इससे इन उद्योगों को बढावा मिलेगा।

ड्रायविंग लायसेंस रिन्यू कराने के लिए जरूरी होगा आधार सत्यापन

नई दिल्ली। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स (Driving licence holders) है या गाड़ी के मालिक (vehicle owners) हैं और ट्रांसपोर्ट विभाग की ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आधार सत्यापन (Aadhaar authentication) जरूरी होगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री 16 तरह की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य बनाने जा रही है। इनमें लर्नर्स लाइसेंस हासिल करना, डीएल का रिन्यूवल, एड्रेस में बदलाव और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंटरनैशनल ड्राइविंग लाइसेंस, नोटिस ऑफ ट्रांसफर और वाहन के मालिकाना हक में बदलाव के लिए आवेदन शामिल है।

सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट ऑर्डर के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पोर्टल के जरिए विभिन्न कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज की सुविधा का लाभ लेना चाहता है तो उसे आधार सत्यापन की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह आधार पंजीकरण की आईडी स्लिप दिखाकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है।

लोगों से मांगे हैं सुझाव

मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट ऑर्डर पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules में ये प्रावधान किए गए हैं। नए रूल्स में व्यवस्था को आसान बनाने के लिए आधार सत्यापन की अनुमति दी गई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि जो लोग आधार सत्यापन से नहीं गुजरना चाहते हैं, उन्हें इन सेवाओं को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से ट्रांसपोर्ट विभाग के ऑफिस जाना होगा।

इससे सरकार को फर्जी दस्तावेजों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही एक से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। देश में रोड सेफ्टी में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आजकल लोगों का जोर कॉन्टैक्टलेस या ऑनलाइन पर जोर है। राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वे इन पहल को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाएं।

NHAI FASTag: अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, जानिए नियमों में क्या हुआ संशोधन

नई दिल्ली। यदि आप नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करते हैं तो फास्टैग (Fastag) तो अपनी कार में लगवाया ही होगा। यदि आपने फास्टैग लगवाया है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कार वाले इसका बेहतर उपयोग कर सके, इसके लिए एनएचएआई ने फैसला लिया है अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन के लिए ही है, कामर्शियल व्हीकल के लिए नहीं।

बैंक नहीं कर सकते अनिवार्य

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। पहले विभिन्न बैंक फास्टैग में सिक्योरिटी डिपोजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने के लिए भी कह रहे थे। कोई बैंक 150 रुपये तो कोई बैंक 200 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखने को कह रहे थे। मिनिमम बैलेंस होने की वजह से कई FASTag उपयोगकर्ताओं को अपने ईएफ्ऊ खाते/बटुए में पर्याप्त शेष होने राशि के बावजूद, एक टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलती थी। इसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर गैर जरूरी नोक-झोंक होती थी।

बैलेंस निगेटिव नहीं है तो गुजरेगी कार

एनएचएआई ने अब फैसला किया है कि यूजर को अब टोल प्लाजा से गुजरने की तब तक अनुमति दी जाएगी, जब तक कि FASTag खाते/वॉलेट में निगेटिव बैलेंस नहीं है। यदि फास्टैग अकाउंट में कम पैसे हैं तो भी कार को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति होगी। भले ही टोल प्लाजा पार करने के बाद फास्टैग अकाउंट निगेटिव क्यों नहीं हो जाए। यदि ग्राहक उसे रिचार्ज नहीं करता है तो निगेटिव अकाउंट की रकम बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल कर सकता है।

इस समय 2.54 करोड़ फास्टैग

इस समय देश भर में 2.54 करोड़ से अधिक फास्टैग के यूजर हैं। इस समय एनएच पर ईएफ्ऊ कुल टोल संग्रह का 80 फीसदी योगदान देता है। इस समय ईएफ्ऊ के माध्यम से दैनिक टोल संग्रह 89 करोड़ रुपये को पार कर गया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2021 से फास्टैग के माध्यम से टोल प्लाजा पर भुगतान अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश भर में टोल प्लाजा पर 100ड्ड कैशलेस टोल प्राप्त करने का लक्ष्य बना रहा है।

बुलियन मार्केट में सोना हुआ सस्ता, जानें रेट

नई दिल्ली। बुधवार को देशभर के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी के दामों में मामूली गिरावट देखने को मिली। बुधवार को 10 ग्राम सोने का भाव 24 रुपये घटकर 48,021 रुपये पर आ गया। कल सोने का भाव 40,045 रुपये पर बंद हुआ था।वहीं, चांदी का रेट 834 रुपये की गिरावट आई। बुलियन मार्केट में चांदी का रेट 69114 रुपये पर खुला। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक 10 फरवरी 2021 को देशभर के सर्राफा बाजारों सोने-चांदी के कमी रही।

IBJA के रेट देशभर में सर्वमान्य

बता दें कि IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में जीएसटी शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते-बेचते समय आप ध्ध्ध् के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ग्ग्ग् देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। सोने-चांदी का करेंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में थोड़ा अंतर होता है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।